रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी हां, सकरी से हसनपुर रोड तक नई लाइन का निर्माण कार्य 100 करोड़ रुपये की लागत पर बजट में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य वित्त वर्ष 1996-97 में शुरू किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का बिछाया जाना

586. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस.एस. सुरजेवाला:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 से आज की तिथि तक मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नयी रेल लाइनें बिछाई गई हैं;

(ख) राज्य में ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस समय नयी रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं;

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान रेल सेवाओं के विस्तार और सुधार से संबंधित कार्य तथा रेल लाइनों को बिछाने से संबंधित किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) मध्य प्रदेश में 1995 से कोई नई लाइन नहीं बिछाई गई है, बहरहाल, परसिया-छिंदवाड़ा का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है।

(ख) इस समय देवास-मक्सी तथा गुना-इटावा खण्डों में कार्य प्रगति पर है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) में रेल लाइन बिछाने से संबंधित का विवरण दिया गया है, मध्य प्रदेश में गाड़ी सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के बारे में यह उल्लेखनीय है कि :-

(i) यात्रियों को यथा संभव कम से कम समय में टिकट जारी करना सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के कुछ स्टेशनों पर माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित स्वत: मुद्रण टिकट मशीनें लगायी गई हैं।

(ii) रेलवे स्टेशनों का विस्तार तथा सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश राज्य के कुछ स्टेशनों पर 1995-96 के दौरान प्रतीक्षा कक्षों/प्रतीक्षालयों, प्लेटफार्म सायवानों, पीने के पानी की सुविधाओं, बैठने के स्थान की व्यवस्था आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था इनमें वृद्धि करने से संबंधित यथापेक्षित कार्य किए गए थे।

(iii) 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित गाड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:-

1. नई गाड़ियां

8403/8404	पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4243/4244	सूरत-वाराणसी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
1517/1518	सतना-मानिकपुर पैसेन्जर
1519/1520	सतना-मानिकपुर पैसेन्जर
1 पी.बी./ 2 पी.बी.	बिलासपुर-पांडरा रोड पैसन्जर
4313/4314	दादर-बरेली एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1029/1030	पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
7611/7612	नांदेड-अमृतसर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1031/1032	पुणे-वाराणसी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
1 आर.बी./ 2 आर.बी.	बिलासपुर-रायपुर पैसेन्जर
33/34	नीमच-चित्तौड़गढ़ पैसेन्जर
69/70	इंदौर-मऊ पैसेन्जर
9303/9304	इंदौर-भोपाल डी.एम.यू. गाड़ी

Banning the use of Polythene Bags

587. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that polythene bags are not bio-degradable and, therefor a cause of environmental degradation;

(b) whether it is also a fact that under the public awareness campaign of Bharat Vikas Parishad, Manali Town Himachal Pradesh has completely replaced polythene bags by paper and jute bags; and

(c) whether Government would consider adivising all States to follow this healthy example and ban the use of polythene bags in their respective territories?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD

NISHAD): (a) Yes, Sir. Polythene bags are not bio-degradable and therefore their, improper disposal causes environmental problems.

(b) As per information received from the Himachal Pradesh State Pollution Control Board, the Bharat Vikas Parishad, Manali Town have made efforts in replacing the polythene bags by paper and jute bags through public awareness campaigns.

(c) No such proposal is under consideration of the Government.

Allocation to Madhya Pradesh from Calamity Relief Fund

588. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Tenth Finance Commission has made any recommendation for the allocation funds to Madhya Pradesh from the Calamity Relief Fund (CRF);

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the ratio of the Central and State Governments' contribution in this regard;

(d) whether the allocation is sufficient to provide relief to the victims of natural calamities in the State; and

(e) if not, what remedial action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) The Tenth Finance Commission had made the following allocations of Calamity Relief Fund (CRF) to Madhya Pradesh :-

Year	Allocation (Rs. in crores)
1995-96	48.21
1996-97	51.08
1997-98	53.89
1998-99	56.65
1999-2000	59.05
Total :	Rs. 268.88

(c) The annual allocation of CRF is shared in the ratio of 3:1 by the Central and the State Governments.

(d) and (e) The Tenth Finance Commission has made the annual allocations of CRF taking into account the average of the aggregatge of ceilings of expenditure on natural calamities for the years 1983-84 to 1989-90 and the amount of CRF for the years 1990-91 to 1992-93. This has also been adjusted for inflation. As such the annual CRF allocations are adequate to take care of the requirements of relief and rehabilitation in the wake of natural calamities. However, if any serious hardship is there it should be brought to the notice of Central Government.

Decline in Kendriya Vidyalaya Results

589. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there has been a gradual decline in the results of the Kendriya Vidyalaya in the CBSE examinations during the preceding three years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken/proposed to be taken by Government for raising the educational standard of Kendriya Vidyalaya?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) Yes, Sir. However, the pass percentage of Kendriya Vidyalayas as a whole continues to be higher than that of the CBSE.

(b) The factors responsible include change in examination pattern, financial and administrative constraints.

(c) Special efforts are on to improve the quality of education in Kendriya Vidyalaya Sangathan through better supervision of academic activities, streamlining of recruitment procedure of teachers, establishment of Zonal Training Institutes for systematic in-service